(3) Every manufacturer of Motor Vehicle is required to submit the prototype of the vehicles manufactured for test by an agency specified by the government, and give certificate of conformity of production on the compliance of the provisions of the Rules including emission standards. The provision has come into force from April 1, 1991.

(4) The mass emission standards for vehicles have been notified under the Motor Vehicles Rules 1989. The standards for petrol driven vehicles have come into force from April 1, 1991 and the standards for diesel driven vehicles shall come into force from April 1, 1992.

(5) Regular enforcement drive is being carried out on the roads of the capital against the vehicles which are not conforming to the prescribed standards.

(6) Directorate of Transport, Delhi Administration has launched an awareness campaign about vehicular pollution, health hazards as well as maintenance of procedures to control vehicular pollution.

(7) Checking facilities have been provided to assess pollution from vehicles as well as facilities for rectification by tuning of the engine.

(8) The government has started a programme of running battery powered buses so as to minimise vehicular pollution and imrove the ambient air quality in congested areas of traffic.

वन संरक्षण अधिनियम के अधीन लंबित परियोजनायें

216. **श्री लक्खीराम अग्रवाल** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रमाण पत्र जारी न किये जाने के कारण मध्य प्रदेश राज्य की कई परियोजनायें लम्बित हैं ;

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर "हां" हो तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इन लंबित परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति देने के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन प्रमाण-पत्र कब तक जारी करने का विचार रखती है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) 31 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत स्वीकृति के लिए प्राप्त केवल 47 प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित थे। उपरोक्त प्रस्तावों में से 28 प्रस्ताव सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित थे, 14 प्रस्ताव खनन से संबंधित थे, 3 प्रस्ताव पारेषण लाइन और 2 प्रस्ताव विविध परियोजनाओं से संबंधित थे।

(ग) राज्य सरकार से सभी अनिवार्य जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अन्तिम निर्णय तेजी से लिया जाता है।

Felling of Forest Trees in Kerala

217. SHRI ARANGIL SREEDHARAN: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that selective felling of forest trees are taking place in some parts of Kerala; and

(b) if so, what steps are being taken to prevent the destruction of forest wealth?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Violation of Pollutions Laws

218. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) what are the names of companies and industries, along with their locations which have been penalised for violation of poilution laws during the last six months; and

(b) what are the details of action taken against each of them ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Construction of hotels at beaches in the country

219. SHRI N.E. BALARAM :
SHRI GURUDAS DAS GUPTA :

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to lift the ban on bulding activity along the waterfront thereby allowing construction of hotels and resorts at six beaches in the country; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH) : (a) and (b) Permission for construction of hotels and beaches will be in terms of Coastal Regulation Zone Notification issued in February, 1991. The norms for such activities depend on the category of Coastal Regulation Zones identified by State Goverrments/Union Territory Administrations and approved by Government of India.

वन रोपण योजनायें

220. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 के वर्ष के दौरान कुल कितनी हेक्टेयर भूमि में वन लगाए गए;

(ख) इस संबंध में इस वर्ष के लिए क्या योजनायें हैं ;

(ग) परती भूमि में वृक्ष लगाने हेतु ग्राम जनता और स्वैच्छिक संगठनों को किस प्रकार की सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है; और

(घ) गत वर्ष के दौरान कितने व्यक्तियों और संस्थाओं ने इस सहायता का लाभ उठाया ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों की वर्ष 1990–91 की उपलब्धियां तथा वर्ष 1991–92 के लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :—

(करोड़ पौध)
(मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र)

	पौध-वितरण (निजी भूमि पर रोपण हेतु)	क्षेत्र (वनभूमि जिनमें सार्वजनिक भूमि भी शामिल है)
उपलब्धियां		
1990–91	125.00	0.74
लक्ष्य		
1991–92	150.00	1.05

(ग) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड अपनी अनुदान सहायता स्कीम के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को परती भूमि विकास तथा वनीकरण कार्यकलाप चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विकेंद्रित पौधशाला स्कीम के अंतर्गत भी पौधशालाएं स्थापित करने के लिए व्यक्तियों तथा संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) वर्ष 1990–91 के दौरान अनुदान सहायता स्कीम के अंतर्गत 114 स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। विभिन्न राज्यों में विकेंद्रित पौधशाला स्कीम के अंतर्गत वर्ष 1990–91 के दौरान कुल 11216 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई।

Population of the Great Indian Rhino

221. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE :
SHRI BEKAL UTSAHI :

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the population of the great Indian one horned rhiro (rhinoceros unicornis) is fast dwindling with atleast 400 of the species slaughtered for their horns since 1974 in Kaziranga sanctuary itself bypoachers